

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 373)

7 श्रावण 1933 (शO) पटना, शुक्रवार, 29 जुलाई 2011

सं0 7/स्था-1-1-5/03सा0-4606

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 अप्रील 2011

विषय:—बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (Assured Career-Progression Scheme) (ए०सी०पी०) का लाभ देने के सम्बन्ध में ।

विभागीय संकल्प संख्या 7/स्था—1—1—5/03 का0 2923, दिनांक 16 अप्रील 2004 के द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को योजना प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों के पश्चात प्रथम ए०सी०पी० तथा प्रथम ए०सी०पी० मिलने की तिथि से पाँच वर्षों के पश्चात द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने का प्रावधान है । उक्त योजना के प्रारंभ होने की तिथि 01 जनवरी 1996 से वास्तविक रूप से है । उक्त संकल्प के अनुसार ए०सी०पी० देने के लिए सेवा अवधि की गणना योजना प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 01 जनवरी 1996 से की जा रही है । जबकि शेट्टी आयोग ने ए०सी०पी० का लाभ हेतु सेवा की गणना सेवा से प्रविष्टि की तिथि से करने की अनुशंसा की है ।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0 2923, दिनांक 16 अप्रील 2004 की कंडिका 3 (1) (2) में निम्न प्रकार से संशोधन करने का निर्णय लिया है :--

असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) एवं असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पदाधिकारी को सेवा में प्रविष्टि के पाँच वर्षों पर प्रथम ए०सी०पी० एवं प्रथम ए०सी०पी० मिलने के पाँच वर्षों के पश्चात द्वितीय ए०सी०पी० इस शर्त के साथ अनुमान्य होगी कि उनको पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई प्रोन्नित्त न मिली हो । ये सुविधा दिनांक 01 जनवरी 1996 से अनुमान्य होगी ।

3. उक्त संकल्प की शेष शर्ते यथावत रहेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से सरयुग प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 373-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in